खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना

3618. **श्री महश्वर सिंह** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में फल तथा सब्जी उत्पादक क्षेत्रों में पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव में हजारों मीटरी टन फल और सब्जियां नष्ट हो जाती है ;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में फल तथा सब्जियों पर आधारित चार प्रतिशत उद्योग स्थापित करने के लक्ष्य हेतु सरकार द्वारा स्वदेशी तथा विदेशी उद्योग-पतियों को प्रोत्साहित करने के लिये कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है ; और

(ग) सरकार निकट भविष्य में कौन-कौन सी अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) :(क) फल तथा सब्जी में फसलोत्तर हानियां अपर्याप्त भंडारण, ढुलाई तथा फसलोत्तर हैंडलिंग व प्रसंस्करण सुविधाओं के कारण होती हैं ।

(ख) और (ग) फल और सब्जियों के बढ़ते हुये प्रसंस्करण, इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में फल तथा सब्जी का प्रसंस्करण शामिल है के लिये अधिक क्षमता का सृजन करने के लिये सरकार ने फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग समेत अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र घोषित किया है तथा प्रौद्योगिकी, विपणन वृद्धि आदि के अनुवर्ती लाभ देश में लाने के लिये 51% तक के विदेशी निवेश के लिये स्वत: मंजूरी प्रदान की है । सरकार ने सभी प्रसंस्कृत फल तथा सब्जी उत्पादों पर उत्पाद शुल्क भी समाप्त कर दिया है तथा इस उद्योग में इस्तेमाल होने वाले पूंजी गत माल पर अनेक वित्तीय राहतें उपलब्ध कराई हैं । इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न विकासात्मक योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रही है । सरकार गैर-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है तथा ठेका कृषि के जरिये बैकवर्ड लिंकेज की स्थापना की अवधारणा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है । इसके अतिरिक्त सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लघु प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित करने के लिये उद्यमियों को प्रशिक्षण देने हेतु खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिये सहायता दे रही है । इसके अलावा; राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड तथा "अपेडा" के पास भी बागवानी फसलों के फसलोत्तर प्रबंध को सुदृढ़ करने के लिये कुछ विकासात्मक कार्यक्रम हैं ।

Applications for setting up food processing industries in Punjab

3619. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have received any applications from the private sector units during the last two years to set up food processing units in Punjab;

(b) if so, the number of such appli cations received and

(c) the steps taken by Government in this respect?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) to (c) During 1993-94 and .1994-95, 14 proposals of 100 per cent Export-Oriented Units. Foreign collaboration, Industrial licences, joint ventures etc. for setting up units in Punjab have been approved by the Government. Apart from these, entrepreneurs have filed 78 Industrial Entrepreneur Memoranda for setting up of variou types of food processing units- in Punjab.